[2015]9 एस सी आर 69

जोगेंद्ररायदव एवं अन्य।

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 2012 की 343)

जुलाई 15,2015

[एस ए बोबडे और आर के अग्रवाल, जे जे]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

उपधारा 319, 227 - के तहत प्रकृति और शक्ति पर चर्चा की गई।

उप धारा 319, 227 - धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़े गए व्यक्ति के मामले में धारा 227 के तहत मुक्ति - अनुमेयता - आयोजित: धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा गया व्यक्ति धारा 227 के तहत मुक्ति के उपाय का हकदार नहीं है क्योंकि यह होगा संहिता की योजना और मंशा के विपरीत - धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए - धारा 319 के तहत तलब किए गए आरोपी धारा 319 के तहत शक्ति के अवैध या अनुचित प्रयोग के खिलाफ कानून के तहत उपचार का आह्वान करने के हकदार हैं। , लेकिन संहिता की धारा 227 के तहत मुक्ति की मांग करके आदेश के प्रभाव को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है।

धारा 319 प्रारंभ से ही अभियुक्त और धारा 319 के अंतर्गत जोड़े गए अभियुक्त के बीच अंतर।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1. सीआरपीसी की धारा 319 के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो आरोपी नहीं है, उसे केवल तभी आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता है, जब साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने कोई अपराध किया है जिसके लिए वह कर सकता है। आरोपियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाए। धारा कहती है कि ऐसी स्थिति में, अदालत "ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्रवाई कर सकती है" जो उसने किया प्रतीत होता है। दूसरी ओर, सीआरपीसी की धारा 227 में प्रावधान है कि यदि न्यायाधीश को लगता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। इसलिए, इन दोनों प्रावधानों का, संक्षेप में, विपरीत प्रभाव पड़ता है। सीआरपीसी

की धारा 319 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है, जो अब तक आरोपी नहीं था और सीआरपीसी की धारा 227 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है। एक आरोपी. [पैरा 6, 7 और 8]

2. शुरुआत से ही एक आरोपी और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जोड़े गए आरोपी के बीच भौतिक अंतर है। शुरुआत से ही आरोपी को आरोपी के रूप में जोड़े जाने से पहले उसे सुना जाना जरूरी नहीं है। हालाँकि, जिस व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है, उसे जोड़े जाने से पहले आवश्यक रूप से सुना जाता है। यदि वह सम्मन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देता है तो अक्सर उसे आगे की सुनवाई मिलती है। यह असंगत और वास्तव में असंगत लगता है यदि दोनों धाराओं का अर्थ यह लगाया जाए कि जिस व्यक्ति को अदालत ने उसके खिलाफ सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी के रूप में जोड़ा है, वह इस आधार पर आरोपमुक्त करने का उपाय प्राप्त कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों में से किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत मजबूत और ठोस सबूत हों। [पैरा 9]

3. साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है; जबकि एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत बरी कर दिया जाता है, एकत्र की गई सामग्री यानी "मामले के रिकॉर्ड और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज" की जांच करने पर, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। वास्तव में, सीआरपीसी की धारा 228 का आदेश यह है कि आरोप तय करने से पहले न्यायाधीश को केवल यह मानना होगा कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है। सबूतों पर विचार करने के बाद किसी आरोपी को जोड़ने का आदेश इस निष्कर्ष पर पहुंचकर रद्द नहीं किया जा सकता है कि सबूतों की सराहना के बिना आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। {पैरा 11]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य **(2014) 3 एससीसी 92: 2014 (2) एससीआर 1;** *अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य* **(2012) 12 एससीसी 406:**

2012(8) एससीआर 970; *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य* **(2008) 3 एससीसी 279: 2007 (13) एससीआर 598 - पर निर्भर।**

केस कानून संदर्भ

2014 (2) एससीआर 1	**पैरा 9**	**पर निर्भर था**
2012(8) एससीआर 970	**पैरा 11**	**पर निर्भर था**
2007 (13) एससीआर 598	**पैरा 12**	**पर निर्भर था**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की आपराधिक अपील संख्या 343

2008 की सीआर विविध संख्या 12193 में उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय और आदेश दिनांक 24/11/2010 से

अपीलकर्ताओं के लिए शिशिर पिनाकी, शैलेन्द्र कुमार, सूर्योदय प्रकाश तिवारी, अमित पवन।

प्रतिवादियों की ओर से गोपाल सिंह, प्रेरणा सिंह, शेखर प्रीत झा, डॉ. ऋचा अवस्थी दुबे।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस ए बोबडे, जे 1 यह चार व्यक्तियों की अपील है जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा गया है (संक्षेप में धारा 302 के तहत अपराध के लिए सत्र परीक्षण एन0 446/2002 में 'सीआरपीसी') भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 149 और 323 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पढ़ें। मुकदमा एक सरयुग यादव की हत्या के संबंध में चल रहा है। 04/06 को /2000, एक मुखबिर द्वारा 8 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149, 302 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। 23/04/2001 को केवल चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। बाद में, एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था 31/01/2003 को भानखर यादव को शामिल किया गया था। चार अपीलकर्ताओं जोगेंद्र यादव, कैलाश यादव, कुसुम पहलवान, बृजेंद्र यादव को पार्टियों से बाहर करते हुए एक अंतिम फॉर्म जमा किया गया था। 18/02/2003 को, मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र और अंतिम प्रपत्र स्वीकार कर लिया। मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

2.मुकदमे के दौरान मृतक की विधवा और दो बेटों की गवाही दर्ज की गई। सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 05/02/2005 को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी किया और उनसे कारण बताने को कहा कि उन्हें आरोपी के रूप में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का अवसर देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को कार्यवाही में शामिल होने के लिए आरोपी के रूप में बुलाया। यह किसी का मामला नहीं है कि ऐसे सम्मन से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। किसी भी मामले में अपीलकर्ताओं के शामिल होने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया, जो लंबे समय से लंबित था। अंततः उन्होंने यह आवेदन वापस ले लिया क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त कर राहत मिल गई थी। प्रतिवादी राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/09/2006 को रद्द कर दिया जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया गया था। आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले की खूबियों के साथ-साथ अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने से पहले ध्यान में रखी गई सामग्री पर कई टिप्पणियाँ कीं। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि जिस आदेश से अपीलकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जोड़ा गया था, उसे चुनौती नहीं दी गई थी और उसे अंतिम बनने की अनुमति दी गई थी। यह वास्तव में सटीक नहीं हो सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ताओं ने वास्तव में आदेश को चुनौती दी थी लेकिन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन वापस ले लिया था।

3. उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि आरोपमुक्त करने का आदेश सीआरपीसी की धारा 319 के तहत पहले दिए गए आदेश को लगभग रद्द कर देता है, जिसके द्वारा आरोपियों को इस अंतिम टिप्पणी में जोड़ा गया था, जिसे हमारे सामने रखा गया है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री शिशिर पिनाकी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 227 का लाभ एक आरोपी द्वारा उठाया जा सकता है, भले ही उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा गया हो क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जोड़ने के प्रभाव से यह है कि वह नया जोड़ा गया आरोपी बन गया है जो सीआरपीसी के तहत उसके लिए उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाने का हकदार है, विशेष रूप से, मुक्ति का उपाय। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 227 और धारा 319 का अर्थ लगाना आवश्यक है

5.सीआरपीसी की धारा 227 और 319 के प्रावधान इस प्रकार पढ़े जाते हैं:

“227. डिस्चार्ज- यदि मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपी को आरोपमुक्त करें और ऐसा करने के उसके कारणों को रिकार्ड करें।

319. अपराध का दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।

(1) जहां, किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही की जा सकती है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, गिरफ्तार या सम्मन किया जा सकता है।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही गिरफ्तारी के अधीन या सम्मन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या सुनवाई के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है, जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय उपधारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है

(ए) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी, और पीड़ित की दोबारा सुनवाई होगी,

(बी) खंड (ए) के प्रावधानों के अधीन, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति आरोपी व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था।

6.0 सीआरपीसी की धारा 319 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आरोपी नहीं है, उसे आरोपी के रूप में तभी जोड़ा जा सकता है, जब साक्ष्य से यह प्रतीत हो कि उसने कोई अपराध किया है, जिसके लिए उस पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा कहती है कि ऐसी स्थिति में, अदालत "ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध

के लिए कार्रवाई कर सकती है" जो उसने किया प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आरोपी नहीं है, वह वहां जोड़े जाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई अपराध किया है। इसके बाद, इसका प्रभाव यह होता है कि न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

7.दूसरी ओर, सीआरपीसी की धारा 227 में प्रावधान है कि यदि न्यायाधीश को लगता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि न्यायाधीश का विचार है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, तो उसे आरोपमुक्त किया जा सकता है, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी जाती है।

8.1t से स्पष्ट है कि इन दोनों प्रावधानों का, संक्षेप में, विपरीत प्रभाव है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाती है जो अब तक आरोपी नहीं था और सीआरपीसी की धारा 227 के तहत शक्ति के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाती है जो एक आरोपी है। आरोपी।

9. हालाँकि, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया था कि सीआरपीसी की धारा 227 के तहत मुक्ति के उपायों का लाभ उठाने के लिए, आवश्यक एकमात्र योग्यता यह है कि व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शुरुआत से ही एक आरोपी और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जोड़े गए आरोपी के बीच कोई अंतर नहीं है, हालांकि, इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों के बीच एक भौतिक अंतर है। शुरुआत से ही किसी आरोपी को आरोपी के रूप में शामिल करने से पहले उसे सुना जाना जरूरी नहीं है। हालाँकि, जिस व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है, उसे जोड़े जाने से पहले आवश्यक रूप से सुना जाता है। यदि वह सम्मन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष और आगे चुनौती देता है तो अक्सर उसे आगे की सुनवाई मिलती है। यह असंगत और वास्तव में असंगत लगता है यदि दोनों धाराओं का अर्थ यह लगाया जाए कि जिस व्यक्ति को अदालत ने उसके खिलाफ सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपी के रूप में जोड़ा है, वह इस आधार पर आरोपमुक्त करने का उपाय प्राप्त कर सकता है कि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है। इसके अलावा, यह तय हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत असाधारण

शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों में से किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत मजबूत और ठोस सबूत हों। अब **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** [(2014) 3 एससीसी 92] में संविधान पीठ के फैसले से यह तय हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए नियोजित सबूत का मानक इससे अधिक है। किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए प्रयुक्त सबूत का मानक। न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के प्रयोजन के लिए कहा, "इसलिए, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, यदि खंडन नहीं किए गए हैं, तो दोषी को दोषी ठहराया जा सकता है।" एक व्यक्ति को मामले में आरोपी के रूप में जोड़ने की मांग की गई। आरोप तय करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की डिग्री के संबंध में इस न्यायालय ने पैरा 100 में देखा:

“100. हालाँकि, ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस अदालत ने सीआरपीसी की धारा 227, 228, 239, 240, 241, 242 और 245 के प्रावधानों से निपटने के दौरान लगातार यह माना है कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध करने का अनुमान लगाने का कोई आधार है या नहीं। अदालत यह तय करेगी कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री आरोपी को अपराध से उचित रूप से जोड़ती है या नहीं। इससे अधिक कुछ भी पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रावधानों से निपटते समय, प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण लागू किया जाना है। अदालत को यह पता लगाना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश की जाने वाली सामग्री अदालत के लिए आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है या नहीं।"

न्यायालय ने पैरा 106 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:-

“106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए, इसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, अगर खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो जाएगी।

10. इस प्रकार यह तर्कसंगत नहीं है कि जिस व्यक्ति को मुकदमे में खड़े होने के लिए आरोपी के रूप में बुलाया गया हो और सबूत के सख्त मानक के आधार पर कार्यवाही में शामिल किया गया हो, उसे निम्नलिखित के आधार पर कार्यवाही से मुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है सबूत के कम मानक जैसे कि अभियुक्त पर आरोप लगाने के लिए अपराध के साथ प्रथम दृष्टया संबंध आवश्यक है।

11. इस दृष्टिकोण को इस तथ्य से और भी बल मिलता है कि साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है; जबकि एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत बरी कर दिया जाता है, एकत्र की गई सामग्री यानी "मामले के रिकॉर्ड और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज" की जांच करने पर, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। वास्तव में यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 228, सीआरपीसी का आदेश यह है कि आरोप तय करने से पहले न्यायाधीश को केवल "यह मानने का आधार होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है"। अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य (2012) 12 एससीसी 406 में बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 227 के स्तर पर साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है (पैरा 17 के अनुसार), इसलिए, यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त आदेश सबूतों पर विचार करने के बाद बनाए गए किसी आरोपी के फैसले को इस निष्कर्ष पर पहुंचकर रद्द नहीं किया जा सकता कि सबूतों की सराहना के बिना आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

12. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि धारा 318 और 227 की योजना पर हमारे द्वारा की गई व्याख्या धारा 227 को एक आरोपी के लिए अनुपलब्ध बनाती है जिसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत जोड़ा गया है, हम इन कारणों से सहमत हैं ऊपर दिया गया है कि यह अनिवार्य रूप से ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसके विपरीत दृष्टिकोण सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक अदालत द्वारा उच्च मानक के सबूत के आधार पर किसी आरोपी को बुलाने के लिए किए गए अभ्यास को पूरी तरह से निष्फल और निरर्थक बना देगा यदि उसी अदालत को बाद में प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर सीआरपीसी की धारा 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करके उसी आरोपी को आरोपमुक्त करना था। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब किए गए आरोपी, धारा 319 के तहत शक्ति के अवैध या अनुचित प्रयोग के खिलाफ कानून के तहत उपचार का आह्वान करने के हकदार

हैं, लेकिन धारा 227 के तहत मुक्ति की मांग करके आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि सीआरपीसी की अनुमति दी जाती है, तो आरोपमुक्त करने की ऐसी कार्रवाई धारा 319 को लागू करने में सीआरपीसी के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगी, जो अदालत को किसी व्यक्ति को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने का अधिकार देती है, जहां ऐसा प्रतीत होता है। सबूत है कि उसने अपराध किया है**। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नुस्ली नेविल वाडिया और अन्य** (2008) 3 एससीसी 279 मामले में इस न्यायालय द्वारा लागू किए गए क़ानून के उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"51....... अधिनियम के प्रावधानों को उचित और प्रभावी तरीके से पढ़ने की दृष्टि से, हमारी राय है कि यदि शाब्दिक व्याख्या की जाती है, तो यह एक विसंगति या बेतुकेपन को जन्म दे सकती है जिससे बचा जाना चाहिए . एक वरिष्ठ न्यायालय को किसी क़ानून की उचित तरीके से व्याख्या करने में सक्षम बनाने के लिए, न्यायालय को स्वयं को एक उचित विधायक/लेखक की कुर्सी पर रखना चाहिए। ऐसा करने पर, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियमों का सहारा लेना होगा जिसके लिए अधिनियम के निर्माण की आवश्यकता इस तरह होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो गया है, जो बदले में वैधानिक योजना के तहत लाभार्थी को आगे ले जाएगा। अशोका मार्केटिंग लिमिटेड में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय द्वारा निर्धारित अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करें।

52. बराक ने "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" पर अपने विस्तृत कार्य में 'उद्देश्य' शब्द के विभिन्न अर्थों की व्याख्या की है। बराक के शब्दों में उद्देश्यपूर्ण निर्माण का उल्लेख करना चर्चा के उपयुक्त होगा:

'हार्ट और सैक्स भी 'उद्देश्य' को एक व्यक्तिपरक अवधारणा के रूप में मानते हैं। 'प्रकट होना' कहें क्योंकि, हालांकि हार्ट और सैक्स का दावा है कि दुभाषिया को खुद को विधायक के स्थान पर कल्पना करनी चाहिए, वे निष्पक्षता के दो तत्वों का परिचय देते हैं: सबसे पहले, दुभाषिया को यह मान लेना चाहिए कि विधायिका उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के इच्छुक उचित लोगों से बनी है उचित तरीके से; और दूसरा, दुभाषिया को इस गैर-खंडन योग्य धारणा को स्वीकार करना चाहिए कि विधायी निकाय के सदस्यों ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों को अच्छे विश्वास से पूरा करने की मांग की है। यह सूत्रीकरण दुभाषिया को लेखक के

व्यक्तिपरक इरादे की जांच करने की अनुमति नहीं देता है, बल्कि लेखक के इरादे की जांच करने की अनुमति देता है, अगर उसने उचित कार्य किया होता।

13. राज्य की विद्वान वकील सुश्री प्रेरणा सिंह ने यह भी प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति धारा 319 के तहत आरोपी है, उसे धारा 227 के तहत मुक्ति के उपाय का लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह योजना और इरादे के विपरीत होगा। सीआर पी सी के

14. ऊपर बताए गए कारणों से हमें इस अनुरोध को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि इससे आरोपी को कोई अनुचित कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार उपलब्ध है।

15. परिणाम में, हम उस अपील में समानता देखते हैं जो खारिज होने योग्य है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपराधिक अपील खारिज की जाती है।

देविका गुजराल　　　　　　　　　　　　　　　　　　की अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में अभय सिंह द्वारा अनुवादित |